

प्रेषक

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
इल्हासी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-3

देहरादून

दिनांक ०७ जनवरी, 2009

विषय:- बालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र पोषित) की मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पत्र संख्या-5/21/2009-PP(PGR) दिनांक 03 दिसम्बर, 2008 (आय-व्यय संलग्न) के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति (100 प्रतिशत केन्द्र सहायित) दिये जाने हेतु रुपये 1,21,380.00 (₹10 एक लाख एकतीस हजार तीन सौ अस्सी मात्र) की धनराशि राज्य के 23 छात्रों (21 नवीन + 02 नवीनीकृत) हेतु अवगुक्त की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त छात्रवृत्ति योजना हेतु बालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखाबुध्दान में अनुदान संख्या-15 के "आयोजनागत" पक्ष में प्राविधानित धनराशि में से उपरोक्त प्रस्तर-01 में उल्लिखित रुपये 1,21,380.00 (₹10 एक लाख एकतीस हजार तीन सौ अस्सी मात्र) की धनराशि को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-205/XXVII(1)/2009, दिनांक 25 मार्च, 2009 के क्रम में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु उत्तराखण्ड के निर्वहन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत बालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए, और किसी भी दश में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए। अवधानहीन मदों में से व्यय करने से पूर्व शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय। योजनामार्गीत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) उक्त आर्कटेड धनराशि किसी मद पर व्यय करने से पूर्व जिसमें वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
- (iii) किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) के आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (iv) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर दिया जाए कि आवश्यकतानुसार आर्कटेड धनराशि के प्रत्येक बिल में साहें वो दस्तावेज आदि के सम्बन्ध में हो अथवा आकरिमिक व्यय के सम्बन्ध में सम्पूर्ण मुख्य/लाघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्पष्टी से अनुदान संख्या-15 "आयोजनागत" शब्द स्पष्ट किया जाए, अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।
- (v) वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर ले कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए आर्कटेड एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

- (VI) मितव्ययता के सम्बन्ध में निगमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मितव्ययिता/अवयवबद्ध की मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति कथना सुनिश्चित करें।
- (VII) यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता हो तो अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (VIII) अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्ताफ़रिफ़ के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (IX) उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
- (X) बी०एम०-13 पर सकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक-2280-अन्य सामाजिक सेवाएँ-800-अन्य व्यय-01-केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र पुरोनिर्धानित योजनाएँ-0102-अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति के मानक मद 21-छात्रवृत्तियाँ और छात्र वेतन के नामे जाता जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० संख्या-680(P)/XXVII(3)09-10 दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न: यथोपरि।

भवदीया,
(मनीषा पवार)
राधिय।

पृष्ठांक संख्या- 5701-23 (1)/XVII-3/2008-07 (85)/2007, तदुद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निजी सचिव, मा० मुख्यमन्त्री, उत्तराखण्ड।
- 2- निजी सचिव, मा० समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- सचिव, उच्च शिक्षा/कला, उत्तराखण्ड।
- 6- निदेशक, क्रीडांगण एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 7- प्रिन्सिपल सचिव, मैनीषाल, उत्तराखण्ड।
- 8- वरिष्ठ क्रीडाधिकारी, इल्हानी-मैनीषाल, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 10- राधिय, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
- 11- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-02, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- उपसचिव, भारत सरकार, अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या 5/21/2008-PP(PER) दिनांक 03 दिसम्बर, 2008 के क्रम में सूचनाएँ प्रेषित।
- 13- बजट, राजकोषीय नियोजन व संसजन नि०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 14- समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 15- राष्ट्रीय सूचना केंद्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 16- आदेश पंजीकृत।

आज्ञा से,
(आर० क० चौहान)
अनु सचिव।